











# सम्पादकीय

## कोरोना के वास्तविक खतरों से आगाह करना जरूरी

देश में कोरोना की भयावह पदचाप फिर सुनाई देने लगी है औ फिलहाल ये आहट धीमी है, लेकिन कब खौफनाक धमक में बदल

जाए, कहा नहीं जा सकता। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार दोपहर 1083 एक्टिव कोरोना केस पाए गए। हालांकि सबह यह संख्या

थी, यानी बढ़ातरी का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 66 और उत्तर प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए हैं दक्षिण और प.भारत के राज्यों के बाद अब पूर्वी और उत्तरपूर्वी राज्यों में भी कोरोना ग्रसित मरीज पाए गए हैं। इससे मने वालों की संख्या भी अब 12 तक पहुंच गई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के 26 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक तब देश में 1010 एकिट्ट केस थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है और साथ ही कोरोना के 4 नए वैरिएंट की पहचान भी हुई है। दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वैरिएंट की पहचान हुई है, उनमें एलएफ 7, एक्सएफजी, जेएन.1 और एनबी.1.8.1 शामिल हैं। अब बाकी जगहों से नमूने लेकर नए वैरिएंट की पड़ताल की जा रही है। कोरोना के नए मामलों को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि नए वैरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी गंभीर खतरा नहीं है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने सोमवार को कहा कि संक्रमण को लेकर गंभीरता की स्थिति अभी तक आमतौर पर हल्की है और चिंता की कोई बात नहीं है। यह सही है कि अब तक महामारी की बात सामने नहीं आई है लेकिन जो अब तक 12 मौतें हुई हैं, क्या उसके बाद भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं है। दृढ़ का जला छाँ भी फूँक-फूँक कर पीता है, यह पुरानी कहावत है। लैकिन हम जले ही नहीं, ज्ञालसे हुए हैं। याद कीजिए कोरोना की दूसरी लहर के भयावह मंजर को। जब अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं कि एक विस्तर मिल जाए, एक ऑक्सीजन सिलर्नेडर मिल जाए, ताकि मरीज की उखड़ती सांसों के आसरा दिया जा सके। एक महिला किस तरह अपने पति को एंबुलेंस में मुँह से सांस देने की कोशिश कर रही थी, वह दृश्य कैसे भूला ज सकता है। शमशानों से देर रात तक चिताओं से लपटें उठा करती थीं कि वहां भी मुर्दे जलाने के लिए कतार लगी रहती थी। जिन शवों को रिटार्म के अनुसार अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ, उन्हें गंगा की गोद में सौंपा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना किसी परिचित की पौत की खबर देखने मिलती थी। कितनी दारुण यांदे हैं, कहां तक पिनाएं? लैकिन क्या हमारी याददाश्ट इतनी कमजोर हो चुकी है कि तीन साल पुरानी बात हम भूल गए हैं सरकार ने पहली लहर के वर्त लापरवाही दिखाई तो उसका भुगतान दूसरी लहर में करना पड़ा। अब फिर से क्या वही लापरवाही दिखाई जा रही है, यह सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी 29-30 मई को उप्र और बिहार दौरे पर रहेंगे उनकी प्राथमिकता इस समय ऑपरेशन सिंदूर को भुनाना है, जिसके लिए वे रोड शो करेंगे। इसके अलावा बिहार चुनाव का मंच सजाना भी भाजपा की तरफ से उनके ही जिम्मे है।

# आहिल्याबाई के लोकहंतकारी कार्यों को इतिहास हमेशा याद रखेगा: सांसद भद्रोही। अहिल्याबाई होल्कर

राजस्ट्र बनामा का प्राइवेट हाथा म सापन के विरोध में उतर आधिकारिक अधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापनपत्र एसडीएम को सौंपा

भदोही। बुधवार को तहसील बार सभागार मे अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। जिसमे निबन्धन विभाग को प्रस्तावित निजीकरण व निबन्धन मित्र बनाये जाने के विरोध में अधिवक्तागण व वैनामा लेखक व स्टाप्प वेंडर द्वारा तहसील में किये जा रहे प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुये निजीकरण प्रस्ताव व निबन्धन मित्र बनाने के बाबत चर्चा की गई और पि मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश सरकार नाम संबोधित एक ज्ञापन प्राइवेट एसडीएम भदोही को सौ गया। मुख्यमंत्री को भेजे गये ज्ञापनपत्र में अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया है कि सरकार डॉ रजिस्ट्री बैनामा को प्राइवेट संस्थान के हाथों में हस्तान्तरित करने व उक्त संस्था द्वारा निबन्धन पि

- सर्वमित्रा सुरजन  
पहले जब सेना के काम का श्रेय सरकरें  
नहीं लेती थीं, तो किसी सैन्य अभियान के  
बारे में जानकारी आधिकारिक सूत्रों के  
जरिए अखबारों, रेडियो, टेलीविजन आदि  
के जरिए जनता को मिलती थी और जनता  
को हमेसा से अपनी सेना पर गर्व रहा। याद  
नहीं पड़ता कि कभी किसी सैन्य अभियान  
पर जनता ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हो।  
लेकिन अब जबकि सरकार से पहले  
डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान कर  
दिया

जब नेतृत्व स्वयं पथ विचलित, भटका हूआ, और निजी स्वार्थों के चंगुल में फंसा हाता है, तब देश कितनी अनावश्यक उलझनों का शिकार होता है, मौजदा दौर इसकी गवाही दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के असली दोषी कहाँ हैं, इसका कुछ पता नहीं है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर से देश में तो मीडिया ने यह सवाल नहीं किया, लेकिन विदेश में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था हमने उनकी पहचान कर ली है। अब इसके आगे क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है, यह गोपनीय ही है और देश फिलहाल यहीं जान पाया है कि आतंकियों की शिखाख कर ली गई है। ये आतंकी पहलगाम तक पहुँचे कैसे, हाथ में बंदूक लेकर जब वो पर्यटकों से भरी बैसरन घाटी में जा रहे थे, तो किसी सुरक्षा एजेंसी की निगाह में कैसे नहीं आए, ये अबूझ पहली बारी हुई है। ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा में विस्पृष्टकों से लदी कार सैन्य वाहन के पास कैसे पहुँची। वैसे तो जम्मू-कश्मीर में चर्चे-चर्चे पर सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था रहती है, लेकिन कम से कम इन दो बड़ी घटनाओं के बत्त यह व्यवस्था किस खोल में छिपी थी, इसके जवाब सरकार से लगातार मार्गे जा रहे हैं और सरकार चुप है। अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों और सभाओं का सिलसिला जारी है, जहां वे ऑपरेशन सिंहूर को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। अपने ऊपर पुष्पवर्षा तक करवा ली, मानो वही पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खत्म करने सीमा पार कर गए थे। इधर भाजपा ने अब एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला

लिया है, जिसमें घर-घर सिंदूर भाजपा पहुंचाएगी। घर-घर शब्द विन्यास शायद नरेन्द्र मोदी को काफी पसंद है। पहले हर-हर मोदी, घर-घर मोदी का शोर किया, फिर घर-घर नल-जल योजना बनाई, इसके बाद हर घर खिरंगा अभियान चला, अब घर-घर सिंदूर खेला शुरू हो गया है।

इस घर-घर के चक्कर में असल में घर में, घरवालों पर क्या बीत रही है, इसका कोई अंदाज सरकार को नहीं है और शायद वह लगाना भी नहीं चाहती। उसकी मंशा किसी भी घटना से राजनैतिक लाभ लेने की बन चुकी है। सैन्य अभियान हो या आतंकी हमला, हर घटना आखिर में भाजपा के लिए बोट जुगाड़ करने का माध्यम बन जाए, बस इतना ही सरोकार नजर आता है। यही कारण है कि समाज में भयंकर अनिश्चितता पसर गई है और सोशल मीडिया के जरिए इसे और बढ़ाया जा रहा है। पहले जब सेना के काम का श्रेय सरकारें नहीं लेती थीं, तो किसी सैन्य अभियान के बारे में जानकारी अधिकारिक सूत्रों के जरिए अखबारों, रेडियो, टेलीविजन आदि के जरिए जनता को मिलती थी और जनता को हमेशा से अपनी सेना पर गर्व रहा। याद नहीं पड़ता कि कभी किसी सैन्य अभियान पर जनता ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हो। लेकिन अब जबकि सरकार से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान कर दिया, जब बार-बार सेना का पक्ष रखने के लिए विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से अधिकारियों को बयान देने सामने आना पड़ा, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर या युद्धविराम के बाद फौरन राष्ट्र को संबोधित न कर, अपनी सुविधा के मुताबिक देश को संबोधित किया, और उसके बाद लगातार अपने अन्य कार्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना शुरू कर दिया। भाजपा और उसके समर्थकों के सौशल मीडिया हैंडल पर जब पिछली सरकारों की आलोचना शुरू हो गई, तो फिर देश में असमंजस और बढ़ गया। बेहतर होता कि तीनों सेनाओं की मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति मुर्मु खुद राष्ट्र को एक बार संबोधित करती और फिर इस मसले पर बाकी किसी मच से चर्चा न होती और



देश की सुरक्षा में लगी एजेंसियों, सेनाओं को उनके काम करने दिया जाता तो फिलहाल जो उलझन भरा माहौल बना है, उससे बचा जा सकता था। लैंकिन भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया। अब इसका खामियाजा वे लोग भगत रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऑफरेशन सिंदूर से जुड़े किसी पहलू पर अपने विचार प्रकट किए। ऐसे कम से कम दो उदाहरण सामने आए हैं। पहला उदाहरण अशोका विश्वविद्यालय के प्रो. अली खान महमूदाबाद का है, जिनकी फेसबुक पोस्ट के आधार पर राज्य महिला आयोग ने शिकायत दर्ज की और उन्हें गिरफतार कर लिया गया। हालांकि उनकी पोस्ट में गलत क्या था, यह अब तक साबित नहीं हुआ है। मगर स्वतंत्र विचार को रोकने की नीतय इसमें साफ नजर आई। इस मामले में प्रो. महमूदाबाद को 18 मई को गिरफतार किया गया था, 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस दिया और अब इस मामले में बनी विशेष जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि वह केवल प्रो. महमूदाबाद पर दायर दो एफआईआर तक ही अपनी जांच समिति रखें। दरअसल प्रो. महमूदाबाद के वकील कपिल सिंघल ने अदालत में उनकी डिजिटल डिवाइस तक अधिकारियों की पहुंच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जिस प्रभाव अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि 'दो एफआईआर रिकॉर्ड' का विषय है। डिवाइस की क्या आवश्यकता है? दायरा बढ़ाने वाले काशिश न करें। एसआईटी राय बनाने वाले लिए स्वतंत्र हैं। बाएं और दाएं मत जाओ। इधर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही प्रकरण घटिया हुआ, जिसमें ऑफरेशन सिंदूर पर एक आलोचनात्मक पोस्ट को एक 19 साल वाली छात्रा ने रिपोर्ट किया, लैंकिन फिर उसे डिलीट भी कर दिया। मगर पुलिस ने उस छात्रा को 9 मई को दर्ज एफआईआर के बाद गिरफतार कर लिया, उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धर्म 152, 196, 197, 299, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया। छात्रा का साथ उसके शैक्षणिक संस्थान भी नहीं दिया और उसे परीक्षा से बचाया रहना पड़ा। जब मामला बॉन्ड हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन और कॉलेज दोनों को आईआर दिखाया। जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा गया 'एक 19 साल की छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफी भी मांगी। इसके बावजूद छात्रा को सुधार वाली भौका देने के बजाय कॉलेज और सरकार

# दूध उत्पाद विशेष अभियान में खाई नमूने संकलित



योगी आदित्यनाथ के आदेशों का असर जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दिखाने लगा है। 15 दिवसीय विशेष अभियान के छठवें दिन तक छोटी-बड़ी बाजारों में दस्तक देकर नमस्ते दर नमस्ते होगी। सहायक प्रभारी आयुर्वेद वीके मालवीय ने कहा विशेष शासन के आदेश पर दूध उत्पादन संबंधित अभियान 24 मई से चल रहा है।

म दस्तक दकर नमून दर नमून  
संकलित कर मिलावटी व नकली  
खाद्य कारोबारियों की धड़कन  
बढ़ा दी।

टीम ने आश्वस्त किया कि छोटी-  
बड़ी बाजारों में बिक रहे संदिग्ध  
पनीर, दूध, देशी धी समेत अन्य  
खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट विपरीत हुई  
तो संबंधित दुकानदारों, व्यापारियों

ना। इन आर चल  
वाले उक्त अभियान में गठित टीम  
शासन की मंशा पर खरा उत्तर कर  
सेहत को बिगाड़ रहे जिम्मेदारों व  
मंशा सफल नहीं होने दिया जाए।  
और शुद्धता का अनुपाल  
प्राथमिकता में रहेगी। टीम  
देवराज सिंह, मानवेंद्र सिंह  
ओमप्रकाश सिंह शामिल रहे।

# कै विरोध में उतरे अधिवक्ता नपत्र एसडीएम को सौंपा

# सेना में दिखने लगा माहला शक्ति का दम

रमण सराफ धमारा  
भारतीय सेना में महिला शक्ति का दम दिखाई देने लगा है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सेना में बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में सेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा युद्ध से संबंधित जानकारी देना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉम्फ्रेंस कर भारत के पराक्रम की तस्वीर को पूरी दुनिया के समने पेश किया और बताया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कैसे और क्या कार्यवाही की। सेना की दोनों महिला अधिकारियों ने ललब समय तक सहायक भूमिका आतक ही सीमित रखा गया।

भारत की तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) में महिलाओं की संख्या को लेकर अगस्त 2023 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि तीनों सेना में 11414 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। थल सेवा में 7054 महिलाएं सेवारत हैं। इनमें 1733 महिला अधिकारी हैं। यह अंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। भारतीय वायु सेवा में 1654 अधिकारी सेवारत है जबकि 155 महिलाएं एयर मेन (अग्निवीर) के रूप में सेवा दे रही हैं। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत हैं जबकि 727 महिलाएं सैलर्स (अग्निवीर) के तौर पर तैनात हैं।

नयात्रत करता है। अब माहताएं डिफेंस भी करती है। टेक्निकल इंटीलिजेंस भी एकत्रित करती है। अभी तक आमने-सामने की लड़ाई में महिलाओं को नहीं भेजा जाता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले की स्क्वाइरन लीडर मोहन सिंह 2016 में भारतीय वायु सेवा की तेजस्वी फाइटर स्पाइटर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले वह मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन भी उड़ा चुकी है। युप कैटर्न सलिया धार्मी वायु सेवा की ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी है जो फ्रैंटलाइन काम्पैक्ट यूनिट की कमान संभाल रही है। फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली भी वह पहली महिला अधिकारी है। भारत की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और थलसेना

सैनिक कार्यवाही की हर दिन प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से देश दुनिया को तो जाग जानकारी प्रदान कर यह दिखा दिया कि भारत में महिला शक्ति भी किसी से कम नहीं है। भारत में सदियों से महिलाओं को मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता रहा है। कहा गया है कि यत्र नार्वसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ अर्थात्: जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। जहां नारियों की पूजा नहीं होती, वहां किए गए इसी तरह 1212 महिलाएं भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में 168 महिलाएं आर्मी डेंटल कार्स में और 3841 महिलाएं मिलिट्री नसिंग सर्विस में कार्यरत हैं। 151 महिलाएं नौसेना के मेडिकल कॉर्प्स में 10 महिलाएं डेंटल कार्य और 380 महिलाएं मिलिट्री नसिंग सर्विस में सेवारत हैं। 274 महिलाएं भारतीय वायु सेवा के मेडिकल कॉर्प्स में पांच महिलाएं डेंटल कॉर्प्स में और 425 महिलाएं मिलिट्री नसिंग सर्विस में एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं। रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें

सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। हम देश में साल में दो बार नवरात्र पर मातृशक्ति रूपी मा दुर्गा की पूजा कर देश दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं है। अब तो हमारी सेना में पुरुषों से कधे से कंधा मिलाकर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपनी उत्कृष्ट क्षमता दिखा दी है। महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो युद्ध भूमि में हर प्रकार की भूमिका निभाने को तैयार नजर आ रही है। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास लंबे संघर्ष और बदलावों से भरा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही महिलाएं भाग्य की संरक्षा और सेवारत है। पहले महिलाओं को शार्ट सर्विस कमीशन में ही लिया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन मिलने लगा है। अब एनडीए की कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटों पर लड़कियां सिलेक्ट होती हैं और वह भी ओपन कंपटीशन में मुकाबला करके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2022 में महिला कैडेट्स के पहले बैच की एंट्री के बाद से अब तक एनडीए में 126 महिलाओं को एडमिशन मिला है। आर्म्ड फोर्सेज में आने के बाद उनके लिए भी अत्यधिक सम्मान दोते रखते हुए आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और ऐसे के हेसाब से सेवानिवृत्त होंगी। साथ ही उन्हें पेशन और सभी भत्ते भी मिलेंगे। 1992 में पांच साल के लिये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। इसके बाद इस सर्विस की अनुधिको 10

सेवा में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। लेकिन सेना में औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति का रास्ता बहुत बाद में खुला। साल 1943 में बनी रानी झांसी रेजिमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। यह पहली बार था जब महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर सक्रिय रूप से योगदान देती रही हैं। उनका करियर प्रोग्रेस वैसा ही होगा जैसा लड़कों का होगा। सर्विस रूट समान होते हैं। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सेना में पूरी तरह जेंडर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। सेना में आज हमारी महिला कॉम्बैट पायलट भी हैं। जो मिसाइल चलती है मोर्चे पर भी याद रखा जायेगा। यह साल के लिए बढ़ाया गया। 2006 में स्टार्ट सर्विस कमीशन को 14 साल कर दिया गया। भारतीय सेना अब महिलाओं को सशत्र बल में नियुक्ति के लिए उनके लिए तय की गई नीतियों को लागू कर प्रोत्साहित करती है। इसके लिए महिलाओं के लिए आर्मी मेडिकल कार, आर्मी डेंटल कार और मिलिट्री नर्सिंग



